जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 225 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 19 जून, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

आज का दिन विदेश नीति की दृष्टि से खट्टा-मीठा दिन रहा भारत के लिए

जी 7 के शिखर सम्मेलन के समापन के दिन मेज़बान कैनडा ने पहल कर, भारत से पुनः कूटनीतिक संबंध जीवित करते हुए, भारत को कैनडा में पुनः हाई कमिश्नर नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया तथा स्वयम् भारत में हाई कमिश्नर नियुक्त करने का निर्णय लिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। एक ऐसे विश्व में, जो नित नये संकटों के कगार पर पहुँच रहा है, में भारत ने कई तरह की कूटनीतिक सफलता और विफलताएँ देखी हैं।

जहाँ एक ओर कैनडा और भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों को बहाल किया और अपने-अपने उच्चायुक्तों को फिर से नियुक्त करने पर सहमति जताई, वहीं दूसरी ओर, अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख, असीम मुनीर को वाइट हाउस में लंच मीटिंग के लिए आमंत्रित करके माहौल को उलझा दिया।

कैनडा में जी7 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद, जहाँ मेज़बान देश के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने-अपने उच्चायुक्तों को फिर से नियुक्त करने पर सहमति जताई, वहीं, भारत को अमेरिका से एक नई निराशा का सामना करना पड़ा।

जैसा कि हमेशा होता है, अमेरिकियों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को अचानक वाइट हाउस में आमंत्रित करके यह दर्शा दिया है कि

- दूसरी ओर अचानक अमेरिका ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर को वाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन पर आमंत्रित कर भारत को चौंका दिया।
- पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारतीय पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद भी ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को आत्मीय भोजन पर आमंत्रित करना, भारत के गले नहीं उतर रहा।
- भारत पहले ही घोषणा कर चुका है कि सीमा पार से की गई आतंकवादी घटना के लिए भारत, पाकिस्तान को ही जिम्मेवार मानेगा तथा पाकिस्तान के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा।
- इन हालात में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से आत्मीयता दिखाना, पाकिस्तान को आतंकवादी घटनाओं के लिए प्रेरित करना लगता है, भारत को।
- अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस अनहोने कृत्य को यह कह कर समझाने का प्रयास किया है कि अमेरिका, पाकिस्तान की भूमि का उपयोग करना चाहता है, ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही के लिए। जैसा कि विदित ही है, पाकिस्तान व ईरान के बीच काफी लम्बी सीमा है।

वे भारत-पाकिस्तान को एक समान स्तर पर रखते हैं। यह स्थिति उस वैश्विक तनावपूर्ण माहौल में सामने आई है, जिसमें अमेरिका इज़रायल-ईरान संघर्ष में हस्तक्षेप करने के प्रति अपना रुझान दिखा रहा है। यह टकराव ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ा रहा है।

अमेरिका द्वारा यह अचानक उठाया गया कदम, पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को आमंत्रित करना, निस्संदेह भारत के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका द्वारा मुनीर को प्रोत्साहित करने से भारत-पाक संबंधों में एक और तनाव पैदा हो सकता है और पाकिस्तान को अपने "प्रॉक्सी युद्ध" को और बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसके तहत वह भारत में आतंकवादी हमले कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से फोन पर हुई फॉलो-अप बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से अमेरिकियों को यह बताया कि भारत अपने आतंकवाद विरोधी संघर्ष को कभी भी "प्रॉक्सी युद्ध" नहीं मानता। मोदी ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

करोना संक्रमण से 24 घंटे में चार की मौत

नयी दिल्ली, 18 जून। देश में पिछले 24 घंटों में 353 करोना सक्रिय मामलों में कमी आने के बाद, कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6483 रह गयी। वहीं, इस अविध में चार और मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या बढ़ कर 113 पहुंच गयी। पिछले 24 घंटों के दौरान 1173 मरीजों के स्वस्थ होने पर इस वायरस से निजात पाने वालों की कुल संख्या 15945 पहुंच गयी है। गौरतलब है कि गत 22 मई को देश में कोराना के मामले सिर्फ़ 257 सक्रिय थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी

- गत 24 घंटे में करोना के एक्टिव केस में फिर से कमी देखी गई। करोना के एक्टिव केस घट कर 6,433 रह गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान करोना संक्रमित चार और मरीज की मौत हो गयी है। महाराष्ट्र में कोरान संक्रमण से दो और मरीज की मौत होने से वहां मतृकों की संख्या 31 पहुंच गयी और राष्ट्रीय राजधानी और केरल में एक-एक और मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या क्रमशः 13 और 36 पहुंच गयी है। इस अवधि में जहां 12 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में करोना के मामलों में वृद्धि देखी गई, वहीं 10 राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी आयी है, जबकि अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से करोना संक्रमण के मामले प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से 35 मिनट बात की

ट्रंप की पहल पर, यह टेलीफोन वार्ता हुई, क्योंकि, जी7 सम्मेलन के दौरान मोदी-ट्रंप मीटिंग भी प्रस्तावित थी, पर, ट्रंप के अचानक चले जाने से यह मुलाकात नहीं हो पाई थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कैनडा से अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बात की, लेकिन उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ से निकाले जा रहे भारतीय छात्रों पर कोई चर्चा नहीं की।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात जी7 सम्मेलन के इतर तय थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को अचानक अमेरिका लौटना पड़ा, जिससे यह बैठक नहीं हो सकी।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर दोनों नेताओं के बीच बुधवार को लगभग 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से संवेदना व्यक्त की थी और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन भी जताया था। उसके बाद बुधवार को यह दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत हुई।

इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी

- प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार से जानकारी दी, कैसे, भारत ने नपे-तुले प्रभावशाली तरीके से पाकिस्तान के हवाई अड्डे व आतंकवादी कैम्पस को नष्ट किया।
- प्र.मंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप से युद्धविराम व व्यापार पर कोई बात नहीं हुई।
- तथा, युद्धविराम का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया, उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया।
- प्र.मंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत अब पाकिस्तान की ओर से प्रेरित आतंकवादी घटना को "प्रॉक्सी वॉर" नहीं मानेगा, बल्कि सीधा युद्ध मानेगा और जवाबी कार्यवाही करेगा।
- राष्ट्रपति ट्रंप ने प्र.मंत्री मोदी को भारत लौटते समय, अमेरिका रूकने का प्रस्ताव दिया, पर, मोदी यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पाये, पूर्व निश्चित कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण।
- मोदी के निमंत्रण पर, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्वाड सम्मेलन के दौरान भारत आने का निमंत्रण स्वीकार किया।

दी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से बताया कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि वह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व मुख्यमंत्री सुखाड़िया के परिवार का भूमि विवाद पुलिस में पहुँचा

पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधु नीलिमा सुखाड़िया ने अपने देवर अरूण सुखाड़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी

उदयपुर, 18 जून। राजस्थान में 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया के परिवार में इन दिनों जमीन विवाद गरमाया हुआ है। मामला थाने तक पहुंच चुका है और भाभी ने देवर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 326(3), 324(4) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमुत्री स्व. मोहनलाल सुखाड़िया की बड़ी पुत्रवधु नीलिमा सुखाड़िया, जो स्व. दिलीप सुखाड़िया की पत्नी हैं, ने उदयपुर के भूपालपुरा थाने में अपने देवर अरूण सुखाड़िया और अरूण के परिचित प्रवीण शर्मा के खिलाफ धोखे से भूखण्ड हड़पने की योजना बनाने का मामला दर्ज करवाया है ।

नीलिमा सुखाड़िया ने एफआईआर में बताया है कि उनके दुर्गानर्सरी निवास स्थान के पास उनका 3958 वर्गफीट

- नीलिमा सुखाड़िया ने कहा कि उसे धमकी दी जा रही है कि प्लॉट छोड़ दे, वर्ना जान से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी ओर अरूण सुखाड़िया के पुत्र दीपक ने कहा कि हमने अपने पक्ष की रिपोर्ट एसपी के समक्ष और थाने में पेश कर दी है।

का एक प्लॉट है। इस प्लॉट पर उन्होंने चार दीवारी की हुई है। उनके ड्राइवर ने 8 जून को देखा कि अरूण सुखाड़िया इस प्लॉट पर आए और 5 मजदूरों से इसकी चार दीवारी तुड़वा रहे थे। अरूण सुखाड़िया खुद वहाँ खड़े होकर निर्देश दे रहे थे। नीलिमा सुखाड़िया ने प्लॉट पर पहुंचकर अरूण सुखाड़िया को रोकने का प्रयास किया। एफआईआर में आरोप है कि इस दौरान अरूण सुखाड़िया ने नीलिमा सुखाड़िया के साथ गाली गलौज की और मारपीट पर उतारू हो गए।

नीलिमा सुखाड़िया ने आरोप लगाया है कि अरूण सुखाड़िया उनकी जमीन पर कब्जा करने की की मंशा रखते हैं। वे उन्हें तथा उनके परिवार को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं। उन्हें अज्ञात लोगों के फोन आ रहे हैं और अज्ञात लोग उनके घर के आस-पास घूम रहे हैं। नीलिमा ने कहा कि वे अकेली रहती हैं, उनकी जान को खतरा है। नीलिमा ने आरोप लगाया कि सुखाड़िया व प्रवीण शर्मा ने प्लॉट बेचने का विज्ञापन निकाला है। यदि उन्हें या उनके घर की सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है तो जिम्मेवार अरूण सुखाड़िया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत अर्नाला नौ सेना में शामिल

नयी दिल्ली, 18 जून। देश में ही बनाया गया अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस 'अर्नाला' बुधवार को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया जिससे नौसेना की मारक क्षमता काफी हद तक बढ जायेगी।

आईएनएस अर्नाला को नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित डॉकयार्ड में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान की

- 1490 टन वजन व इस 77 मीटर लम्बे युद्धपोत का नाम महाराष्ट्र के एक तटवर्ती किले के नाम पर रखा गया है।

उपस्थिति में नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल किया गया। यह देश में ही बनाये जाने वाले इस तरह के 16 युद्धपोतों में से पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है।

जनरल चौहान ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय नौसेना अब 'खरीददार' के बजाय "मैन्युफैक्चरिंग" करने वाली नौसेना के रूप में उभर रही है। अभी देश में बड़ी संख्या में युद्धपोत तथा अन्य नौसैनिक पोत निर्माणाधीन हैं जिससे भारत पोत निर्माण में एक दुर्जेय शक्ति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मोदी कैनडा यात्रा से लौटते ही सर्वदलीय बैठक आयोजित करें'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका से लौटते ही सभी राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर क्या बात की, और उन्हें पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रंप को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि भारत, पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के ट्रंप के साथ लंच करने की खबरों से भारत अप्रसन्न है।

कांग्रेस ने जनरल असीम मुनीर के ट्रंप के साथ लंच की खबर को "एक बड़ा कूटनीतिक झटका" बताया।

कांग्रेस के महासचिव एवं संचार विभाग प्रमुख जयराम रमेश ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह "पहलगाम समीक्षा समिति" का गठन करे, जैसे कारगिल युद्ध के तीन दिन बाद "कारगिल समीक्षा समिति" बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता के.सुब्रह्मण्यम (विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पिता) ने की थी।

- कांग्रेस की मांग है, प्र.मंत्री मोदी इस बैठक में साझा करें कि 35 मिनट की टेलीफोन वार्ता में उन्होंने क्या-क्या कहा ट्रंप को।
- ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने (प्र.मंत्री मोदी ने) उस बात का भी पुरजोर खण्डन किया, जो ट्रंप अब तक 14 बार कह चुके है कि उन्होंने व्यापार का दबाव बनाकर, भारत-पाक युद्ध में "सीज़फायर" करवाया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को संसद में डॉनल्ड ट्रंप के उन दावों का खंडन करना चाहिए, जिनमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के लिए उन्होंने व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया।

यह टिप्पणी उस समय आई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की और स्पष्ट किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमले रोकने का निर्णय इस्लामाबाद के अनुरोध पर लिया था, न कि अमेरिकी मध्यस्थता या किसी व्यापार समझौते के प्रस्ताव के कारण।

जयराम रमेश ने कहा कि तीसरा बड़ा झटका यह है कि ट्रंप ने 14 बार यह दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और युद्धविराम लाने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने कहा, "वे (ट्रंप) कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखते हुये, व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने यह बात 14 बार कही और प्रधानमंत्री ने 10 मई से अब तक कुछ नहीं कहा। यह तिहरा झटका है।"

मोदी-ट्रंप बातचीत पर रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से यह कहा बताते हैं कि व्यापार का ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना-देना नहीं है और मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने कहा, "जब लौटें, तो तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और बताएं कि राष्ट्रपति ट्रंप से 35 मिनट की बातचीत में क्या-क्या बातें हुई।"

रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रंप के 14 बार किए गए दावों पर चुप्पी तोड़ने में 37 दिन लग गए और दोहराया कि मोदी को देश को विश्वास में लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, "असीम मुनीर का ट्रंप के साथ लंच और कुरिल्ला (अमेरिकी व्यापार सलाहकार) की टिप्पणियाँ प्रधानमंत्री की कूटनीति के लिए बड़ा झटका हैं। मोदी सरकार के कूटनीति दिखावे पर आधारित रही है। ये प्रत्याशित झटके हैं। हमें दिखावे के बजाय, ठोस कूटनीति पर अधिक ध्यान देना चाहिए।"

रमेश ने कहा, "देश को विश्वास में लेने और सामूहिक इच्छाशक्ति तथा संकल्प को मजबूत करने का कोई विकल्प नहीं है।"

उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया कि वे "डिवाइडर-इन-चीफ हैं और सवाल उठाया कि वे विपक्ष के नेताओं को विश्वास में क्यों नहीं लेते।

निजी वाहनों के लिए जारी होगा वार्षिक फास्टैग पास

नयी दिल्ली, 18 जून। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजाओं पर बढ़ ते विवादों तथा भीड़ को कम करने और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निजी वाहनों के लिए तीन हजार रूपये का वार्षिक फास्टैग पास शुरू करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को खुद यह जानकारी

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी तथा बताया कि 3000 रु का यह पास एक वर्ष या 200 यात्राओं, जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगा।

दी। यह पास आगामी 15 अगस्त से उपलब्ध रहेगा और सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से 3,000 रूपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी क्रोएशिया पहुंचे

जागरेब, 18 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर बुधवार को यहां क्रोएशिया की राजधानी जागरेब पहुंच गये।

जागरेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेन्कोविच ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी कैनड़ा में जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने

- प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंतिम पडाव पर हैं। क्रोएशिया से देर रात वे स्वदेश रवाना हो जाएंगे।

के बाद जागरेब पहुंचे हैं। यात्रा की शुरूआत में वे सबसे पहले साइप्रस गये थे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आज शाम को होगी। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। इसके बाद देर रात मोदी स्वदेश रवाना हो जायेंगे।

प्रधानमंत्री ने जी-7 देशों की शिखर बैठक से इतर भागीदार देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

22 मुस्लिम बाहुल्य देशों ने एक आवाज़ में इज़रायल की भर्त्सना की, ईरान के खिलाफ युद्ध की कार्यवाही के लिए

इन देशों में कई वो देश भी शामिल हैं, जो अमेरिका से अच्छे संबंध रखते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। एक असाधारण एकता का प्रदर्शन करते हुए, 22 मुस्लिम बहुल देशों ने, राजनीतिक मतभेदों और राजनयिक निष्ठाओं के बावजूद, इज़राइल की ईरान के खिलाफ बढ़ ती सैन्य कार्रवाइयों की संयुक्त रूप से निंदा की है। यह बयान मिस्र के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया, जो क्षेत्रीय सहमति का एक दुर्लभ उदाहरण है। इसमें वे देश भी शामिल हैं, जो परंपरागत रूप से इज़रायल के साथ औपचारिक संबंध रखते हैं या जो ईरान के विरोध में खड़े हैं, परंतु इस समय व्यापक मध्य पूर्व संघर्ष की आशंका के चलते एकजुट हो गए हैं।

बयान में 13 जून 2025 से शुरू हुए इज़रायली सैन्य हमलों की निंदा की गई, जिनमें ईरान की परमाणु सुविधाओं, मिसाइल ठिकानों, सैन्य कर्मी और परमाणु वैज्ञानिक को लक्ष्य बनाया गया। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह सैन्य अभियान ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए किया गया है। तथापि, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देशों के साथ-साथ तुर्की, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी देशों सहित, 22 देशों ने इस कदम को "पूर्ण रूप से अस्वीकार्य और निंदनीय" बताया और चेतावनी दी कि यह क्षेत्र को व्यापक युद्ध की ओर ले जा सकता है।

इस संकट के मूल में ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर वर्षों से चला आ रहा तनाव है। तेहरान और

- सऊदी अरब, यू.ए.ई., कतर, ओमान, बहरीन के अलावा तुर्की, इण्डोनेशिया व कई अफ्रीकी देश भी इस मुद्दे पर इज़रायल के विरोध में उतरे हैं।
- इन देशों ने इस बात पर भी भारी चिंता जताई कि अब यह संघर्ष दो देशों के बीच छुट-पुट लड़ाई नहीं है, बल्कि सारे खाड़ी देशों व विश्व के अन्य देशों को भी युद्ध में धकेल देगा।
- अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ सख्त रूख अपनाया है तथा अमेरिका ने अपने जलपोत व अन्य आक्रमक सैन्य सामान की सुरक्षा की व्यवस्था की है, क्योंकि, अमेरिका को भय है कि अन्ततोगत्वा, चाहे बेमन से, उसे इस युद्ध से जुड़ना पड़ सकता है तथा यह युद्ध लम्बा चल सकता है।

वाशिंगटन के बीच चल रही बातचीत, जिसमें इस वर्ष की शुरुआत में थोड़ी प्रगति हुई थी, अब खुले सैन्य संघर्ष के कारण विफल हो गई है। ईरान, जो लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को नागरिक उद्देश्यों के लिए बताता रहा है, ने जवाब में इज़राइली क्षेत्रों पर अनेक मिसाइल हमले किए हैं, जिससे लंबे समय तक संघर्ष की चिंताएं और बढ़ गई हैं।

सम्पूर्ण मध्य पूर्व में हवाई यातायात बाधित हो गया है और नागरिक विमान सेवाओं को संभावित संघर्ष क्षेत्रों से हटाकर अन्य मार्गों पर भेजा जा रहा है। कई देश, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, अब इस युद्ध के भूराजनीतिक और आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे हैं, जो अब केवल द्विपक्षीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलने की आशंका पैदा कर रहा है।

इन 22 देशों के संयुक्त बयान में इज़रायली हमलों को तुरंत रोकने की अपील की गई है और सभी क्षेत्रीय पक्षों से कूटनीति की राह पर लौटने का आग्रह किया गया है। बयान में कहा गया, हम इस समय मध्य पूर्व में बढ़ ते तनाव के बीच ईरान पर इज़रायली हमलों को तत्काल रोकने की अनिवार्यता पर ज़ोर देते हैं। हम व्यापक युद्धिवराम और शांति की बहाली की मांग करते हैं, साथ ही संघर्ष की इस खतरनाक वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, जो पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

एक उल्लेखनीय बदलाव में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने क्षेत्र में परमाणु निरस्त्रीकरण के महत्व को भी रेखांकित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK